website : khabarplatform.in

RNI MPHIN /2023/ 90851

खबर प्लेटफार्म

वर्ष 03 अंक 36 जबलपुर, सोमवार 02 से रविवार 08 फरवरी 2026 संजय सागर सेन-प्रधान सम्पादक हिन्दी साप्ताहिक मूल्य 01 रुपये पृष्ठ-4

बजट : आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, इनकम टैक्स में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। वे संसद में 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही हैं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ। सीतारमण ने इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं भी नहीं कीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 2.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने और ऋण-जीडीपी अनुपात घटाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। हालांकि, इस बजट का सबसे कमजोर पक्ष वही है, जो आम नागरिक की रोजमर्रा की चिंता से जुड़ा है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह की बड़ी राहत न मिलना मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक रहा। महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च के दबाव से जूझ रहा मध्यम वर्ग इस बार भी 'अप्रत्यक्ष लाभ' के भरोसे छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर, केन्द्रीय बजट 2026-27 को आज की राहत से ज्यादा कल की तैयारी यानि 'राहत कम, रफ्तार ज्यादा' वाला बजट कहा जा रहा है। क्योंकि, आम आदमी को तुरंत बड़ी राहत भले न मिली हो, लेकिन सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन पर बड़ा दांव खेला है।

बड़ी घोषणाएं

- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।
- युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
- आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। जामनगर में डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।
- मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत टैक्स किया गया है।
- एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत टैक्स किया गया है। एम्पलॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 प्रतिशत टैक्स होगा। 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।

क्या-क्या हुआ सस्ता

1. कैंसर की दवाइयां सस्ती : 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म।
2. माइक्रोवेव ओवन सस्ते : पुर्जों पर ड्यूटी घटी, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी।
3. ईवी बैटरी और सोलर पैनल सस्ते : इसे बनाने का कच्चा माल हुआ टैक्स फ्री।
4. जूते, कपड़े सस्ते हो सकते हैं : एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर छूट।
5. विदेश घूमना सस्ता होगा : सरकार ने टैक्स घटाकर 2 प्रतिशत किया।
6. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता : पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटी।
7. विदेशी सामान मंगाना सस्ता : सरकार ने विदेश से सामान पर लगने वाले टैक्स को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।
8. मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन।

क्या होगा महंगा?

1. शराब के लिए इस्तेमाल होने वाले एल्कोहल पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) एक फीसदी से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया। यानी शराब महंगी होगी।
2. कबाड़ पर भी टीसीएस को एक प्रतिशत से दो प्रतिशत किया गया। यानी कबाड़ महंगा होगा।
3. खनिजों, खासकर कोयले और लौह अयस्कों पर टीसीएस को एक प्रतिशत से दो प्रतिशत किया गया। यह महंगे होंगे।
4. आयकर की गलत जानकारी देने पर टैक्स की राशि का 100 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान।
5. चल संपत्ति का खुलासा न करने पर जुर्माना लगेगा।
6. स्टॉक ऑप्शन्स और फ्यूचर ट्रेडिंग महंगी होंगी। लेन-देन पर टैक्स 0.02 से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया गया।

चुनौतियों से निपटने का प्रावधान नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्रीय बजट को नीतिगत खालीपन, दूरदर्शिता तथा दिशाहीन करार देते हुए कहा है किआर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खरगे ने कहा बजट 2026-27 से साबित होता है कि इसमें देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किए गये हैं। बजट में चुनौतियों का ठोस समाधान करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गये हैं। सरकार का मिशन मोड अब चुनौती मार्ग बन चुका है और रिफॉर्म एक्सप्रेस किसी भी सुधार वाले स्टेशन पर रुकने से कतराता दिख रहा है।

देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। - नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

बेरोजगार युवा, गिरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग, परेशान किसान सभी को नजरअंदाज किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है।
- राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष

केन्द्र सरकार के पास पूर्ण सत्ता होने के बावजूद इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि विकास और वृद्धि के लिए बजट तैयार करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। - गौरव गोगोई, कांग्रेस सांसद

पांच उम्मीदें जो टूट गईं

इस बजट से मिडिल क्लास को खासी उम्मीदें थीं। आयकर में छूट और महंगाई पर काबू जैसे ऐलान का इंतजार कर रहे थे। सीनियर सिटीजन को भी रेल किराये में छूट समेत की उम्मीदें थीं। लेकिन आम आदमी से जुड़े कई बड़े ऐलान नहीं हुए।

1. पिछले बजट में नए आयकर रिजीम के तहत आम टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर '0' टैक्स का ऐलान किया गया था, जिसकी लिमिट बढ़ाकर इस बार 14 लाख किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है।
2. नए टैक्स सिस्टम के तहत एनपीएस, पीपीएफ और ईएलएसएस जैसी योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट दिए जाने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यह सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही छूट के योग्य होंगे।
3. किसानों को उम्मीद थी कि पीएम किसान योजना का बजट बढाया जाएगा और इसको 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार के बजट में इसे नहीं बढ़ाया गया है। वहीं फसलों के एमएसपी को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है।
4. उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बीमा योजना सपोर्ट और रेलवे ट्रेन टिकट में रियायतें दी जा सकती है। लेकिन बजट में सिर्फ रेल कॉरिडोर का ही ऐलान किया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
5. बजट में शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका दिया गया है। एफएंडओ ट्रेडर्स के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ा दिया गया है। जबकि उम्मीद थी कि इसमें कटौती हो सकती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया।

संविदाकर्मियों की भूमिका हनुमान जी के समान है: डॉ. मोहन यादव

संविदाकर्मियों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व ,कीं महत्वपूर्ण घोषणाएं

भोपाल ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संविदाकर्मियों के श्रम और विश्वास पर ही राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हो रही है। संविदाकर्मियों की भूमिका हनुमान जी के समान है। आपके श्रम और साझेदारी ने ही शासन-प्रशासन की व्यवस्था बनाई रखी है। संविदाकर्मी अनुबंध से अवश्य आते हैं, किन्तु व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय या तकनीकी सेवाएं मैदानी स्तर पर सर्वे, मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन में संविदा भाई-बहन हर जगह व्यवस्था के भरोसेमंद स्तंभ बनकर खड़े हैं। संविदाकर्मियों ने जिस निष्ठा से काम किया है, उसने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा पद से बड़ी है। संविदाकर्मी राज्य सरकार का कार्यबल ही नहीं, हमारा आत्मबल भी हैं। भारतीय मजदूर संघ के देश के हित में करेंगे काम के वाक्य को हमारे साथी चरितार्थ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को टीटी नगर दशहरा मैदान में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा भारत माता और श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यक्रम स्थल आगमन पर पुष्प वर्षा कर और बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया।

संविदाकर्मियों की मांगों पर रखा जायेगा पूरा ध्यान

- 10 वर्ष से अधिक अनुभवी संविदाकर्मियों को नियमित पदों पर संविलियन की अभी तक 50 प्रतिशत पदों के लिए प्रक्रिया जारी है, इस दिशा में आगे और काम किया जाएगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग संविदा नीति-2023 के अंतर्गत सभी कंडिकाओं का केंद्र और राज्य पोषित परियोजनाओं में अक्षरश: क्रियान्वयन किया जाएगा।
- संविदा नीति-2023 के अंतर्गत सभी विभागों में संविदा कर्मियों के लिए एनपीएस, ग्रेज्युटी, स्वास्थ्य बीमा लाभ,लागू करने के संबंध में नीतिगत निर्णय कराया जाएगा।
- विभिन्न विभागों, योजना, परियोजना में पदस्थ संविदा कर्मचारियों की विसंगतिपूर्ण समकक्षता के निर्धारण के लिए अभ्यावेदनों का निराकरण, गठित समिति द्वारा समय-सीमा में किया जाएगा।
- कृषि विभाग की आत्मा योजना, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों में संविदा नीति-2023 के तहत समकक्षता का निर्धारण किया जाएगा।

सरकार संविदा कर्मियों के सभी मुद्दों का समाधान निकालेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारी सरकार संविदा कर्मियों के अधिकारों के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के सेवा सुधार, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थिति और भविष्य के सुधारों पर पहले भी सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, भविष्य में भी उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारी सरकार संविदा कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी मुद्दों का समाधान निकालेगी। संविदा कर्मचारियों के लिए जो भी निर्णय हो सकते हैं, उससे अधिक करने का प्रयास करेंगे। नियम, न्याय और वित्तीय संतुलन के दायरे में रहते हुए संविदाकर्मियों की कठिनाइयों का हल निकाला जाएगा। मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के साथ समन्वय करते हुए सभी कठिनाइयों का समाधान इस प्रकार किया जाएगा, जिससे संविदाकर्मियों का सम्मान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। संविदाकर्मियों की उचित मांगों पर राज्य सरकार संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ उनका सहयोग करेगी।

आतंकवाद साझा खतरा : जयशंकर

आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को वैश्विक स्तर पर अपनाये जाने की जरूरत

नयी दिल्ली। विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर ने आतंकवाद को साझा खतरा बताते हुए इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने तथा आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को वैश्विक स्तर पर अपनाये जाने की जरूरत पर बल दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि बदलाव के दौर से गुजर रही वैश्विक व्यवस्था का असर पश्चिम एशिया में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और इससे निकटता के मद्देनजर भारत भी इससे स्वाभाविक रूप से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना को आगे बढ़ाना आज एक साझा प्राथमिकता बन चुका है। डा. जयशंकर ने शनिवार को यहां भारतङ्कअरब विदेश मंत्रियों की द्वितीय बैठक में अपने वक्तव्य में कहा कि सभी तरह का आतंकवाद दोनों क्षेत्रों के समक्ष एक साझा खतरा है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद विशेष रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के मूल

सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद से प्रभावित समाजों को आत्मरक्षा का अधिकार है और वे स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग करेंगे। आतंकवाद से मिलकर निपटने तथा इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, च्च यह आवश्यक है कि हम इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त करें। आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना एक अडिग और सार्वभौमिक मानदंड होना चाहिए। वैश्विक उथल -पुथल के दौर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक व्यवस्था विभिन्न कारणों से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है ।

अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा की बंगाल इकाई के नेताओं के साथ बैठकें की

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विगत दिवस देर रात कोलकाता पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की। श्री शाह जैसे ही कोलकाता पहुंचे, वे सीधे हवाई अड्डे से न्यू टाउन के एक होटल में गए। उन्होंने वहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। मौजूद लोगों में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी सुनील बंसल, मंगला पांडे, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देब और अमित मालवीय शामिल थे। नेताओं ने हालांकि बैठक की खास बातों पर टिप्पणी करने से परहेज किया लेकिन भाजपा ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से चुनाव की तैयारियों, राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर केंद्रित थी। गौरतलब है कि श्री शाह ने लगभग एक महीने पहले पश्चिम बंगाल की अपनी पिछली यात्रा के दौरान राज्य के नेताओं को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। वह शनिवार की सुबह उत्तर 24 परगना के बैरकपुर जाएंगे, जहां आनंदपुरी मैदान में एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे।

अविमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य

देहरादून। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद अब यूपी से निकलकर उत्तराखंड तक पहुंच गया है। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह जहां साफ कह चुके हैं कि सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती। वहीं, बद्रीनाथ धाम से जुड़ी डिमरी पंडितों की पंचायत अविमुक्तेश्वरानंद को ही शंकराचार्य मान रही। यही वजह है कि उन्हें गाडू कलश (तेल कलश) यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया जा चुका है। डिमरी समाज का कहना है कि उनका फैसला किसी मंत्री या सरकार के बयान के आधार पर नहीं, सनातन परंपरा के अनुसार होता है। शंकराचार्य की पहचान आस्था और परंपरा से तय होती है, न कि राजनीतिक या प्रशासनिक रुख से।

ममता बनर्जी ने दायर की मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ याचिका

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक के ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। विश्लेषक इस कदम को पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते टकराव के रूप में देख रहे हैं।

न्यायालय के सूत्रों के अनुसार, इस मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ बुधवार को राज्य के संबंधित एसआईआर मामले की सुनवाई करने वाली है। इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डोला सेन और डेरेक ओब्रायन के साथ कृष्णा नगर की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसी मुद्दे पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

संपादकीय

बजट के वक्त कुछ सवाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निरंतर नौवां बजट लोकसभा में पेश किया है। देश की महिला वित्त मंत्री और यह निरंतरताञ्चाकई एक कीर्तिमान है। 2026-27 के बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, किसके हिस्से, कितनी राशि आवंटित की गई है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के क्या अंतर्विरोध और खामियां हैं, करीब 378 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में आम आदमी कितना सम्पन्न है, उसकी जेब में कितना पैसा है, इनमें से कुछ विसंगतियों का विश्लेषण आज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट देश के सामने है, लेकिन हम पहले कुछ बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। बेशक हम चौथी आर्थिक महाशक्ति हैं, लेकिन भारत में आज भी प्रति व्यक्ति आय 2.34 लाख रुपए सालाना क्यों है? और देश विश्व में 140वें स्थान पर क्यों है? बीते पांच साल में हमारा निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है और आयात का बोझ बढ़ता जा रहा है? नतीजतन 2024-25 में व्यापार घाटा 24 लाख करोड़ रुपए है। बीते 10 सालों के दौरान विदेशी निवेश में गिरावट क्यों जारी है? ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में विदेशी निवेश 9730 करोड़ रुपए था, जो 63 फीसदी कम हुआ है। घरेलू बड़ी कंपनियां भी अपने देश में निवेश बहुत कम कर रही हैं, जबकि विदेशों में उनका निवेश 14 अरब डॉलर से बढ़ कर 24 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कारपोरेट का यह नकारात्मक रुख क्यों है? 'आर्थिक सर्वेक्षण' में हमारी जीडीपी की विकास दर 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी का अनुमान दिया गया है, लेकिन डॉलर की तुलना में हमारी मुद्रा 'रुपए' का अवमूल्यन देखें, तो यह विकास दर मात्र 1.5 फीसदी बनती है। क्या इसी आधार पर भारत 2047 तक 'विकसित राष्ट्र' बन सकता है? हमारे 11 बड़े राज्यों पर अभूतपूर्व कर्ज है और देश पर भी कर्ज का बोझ करीब 225 फीसदी बढ़ गया है, नतीजतन प्रत्येक भारतीय पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। अर्थव्यवस्था की कौन-सी गुलाबी तस्वीर पेश की जा रही है? कुछ और तथ्य गौरतलब हैं। एक साल में देश की आईटी की 5 प्रमुख कंपनियों में मात्र 17 नौकरियां दी गई हैं। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की जो दरें हमारे सामने आती हैं, वे सरकारी और अर्द्धसत्य हैं। देश में करीब 1.20 करोड़ गिग वर्कर्स कार्यरत हैं।

उनमें से 40 फीसदी औसतन 15,000 रुपए माहवार ही कमा पाते हैं। यानी 500 रुपए प्रतिदिनञ्न्यूनतम दिहाड़ी से भी कमञ! बीमा क्षेत्र दुनिया में सबसे निचले स्तर पर है, क्योंकि लोग बीमे को लेकर जागरूक ही नहीं हैं और देश में बीमा बहुत महंगा है। बहरहाल वित्त मंत्री ने बजट में कुछ अहं घोषणाओं, योजनाओं, कारिडोर, पार्क संबंधी प्रस्ताव रखे हैं। उनमें विकास पर सरकारी पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का रिकार्ड आबंटन किया गया है। सरकार ने ग्लोबल बायो फार्मा हब और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए क्रमशञ 10,000 और 40,000 करोड़ रुपए तय किए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है। हालांकि जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान घटकर 12-13 फीसदी तक आ गया है, लेकिन बजट में 'चैम्पियन एमएसएमई' के निर्माण की बात कही गई है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के बढ़ावे और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए 2000 करोड़ रुपए का टॉप अप भी घोषित किया गया है। बजट में दुर्लभ अर्थ खनिजों, 7 हाईस्पीड रेल के कॉरिडोर और 20 नए जलमार्गों के जरिए बुनियादी ढांचे को संबोधित किया गया है।

केंद्रीय बजट 2026-27 : तात्कालिक राहत से आगे, दीर्घकालिक विकास की बुनियाद

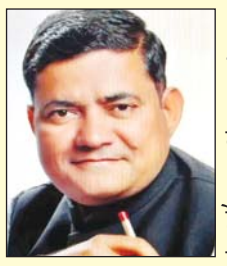

दीपक पचौरी

1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 केवल एक वार्षिक आय-व्यय विवरण नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक दिशा और विकास दर्शन को स्पष्ट करने वाला दस्तावेज है। यह बजट ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से घिरी हुई है, विकसित देश मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, और विकासशील देशों के सामने रोजगार, निवेश तथा सामाजिक संतुलन की दोहरी चुनौती है। ऐसे परिदृश्य में यह बजट भारत को स्थिरता, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास करता दिखाई देता है।

बजट की समग्र रूपरेखा

केंद्रीय बजट 2026-27 का मूल स्वर पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, विनिर्माण एवं तकनीक, तथा मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। सरकार ने तात्कालिक लोकलुभावन घोषणाओं से बचते हुए आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दी है। इस बजट में लगभग 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वहीं राजकोषीय घाटे को लगभग 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखकर सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संकेत दिया है। यह संतुलन बताता है कि सरकार विकास और आर्थिक जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है।

किसे क्या मिला : बजट की क्षेत्रवार समीक्षा

1. बुनियादी ढांचा : विकास की रीढ़

बजट का सबसे मजबूत पक्ष बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश है। 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा से देश की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है।

सड़क, रेल, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, इनलैंड वाटरवे और कोस्टल शिपिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से परिवहन लागत घटेगी और व्यापार में तेजी आएगी। यह निवेश न केवल निर्माण क्षेत्र को गति देगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगा।

2. विनिर्माण और तकनीक आत्मनिर्भर भारत की दिशा

बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत चिप निर्माण को नया बल दिया गया है। रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, बायो-फार्मा शक्ति, केमिकल और टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएँ उच्च-मूल्य उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगी। एमएसएमइ के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड छोटे उद्योगों को विस्तार और प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाएगा। इन पहलों से भारत केवल आयात पर निर्भर बाजार नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा।

3. कृषि और ग्रामीण भारत

कृषि क्षेत्र में बजट का दृष्टिकोण केवल अनुदान तक सीमित नहीं है, बल्कि मूल्य संवर्धन और ग्रामीण उद्यमिता पर आधारित है। मछलीपालन, पशुपालन, डेयरी, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा। जल संरक्षण, अमृत सरोवर और सिंचाई परियोजनाएँ।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार से जुड़ाव

इन प्रयासों से किसानों की आय में स्थिरता आएगी, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी।

4. मध्यम वर्ग और करदाता

इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग की अपेक्षाएँ अधिक थीं, परंतु इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। प्रत्यक्ष कर राहत सीमित रही। हालांकि सरकार का तर्क है कि स्थिर कर व्यवस्था, कम महंगाई, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन से मध्यम वर्ग को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह बजट तत्काल राहत के बजाय भविष्य की आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित है।

5. स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र

मानव संसाधन विकास इस बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान तीन आयुर्वेदिक एआइआइएमएस की स्थापना कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता करने की पहल हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की योजना, जिससे बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। स्वस्थ और शिक्षित समाज ही दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव रखता है, और यह बजट उसी दिशा में निवेश करता दिखता है।

देश के विकास में बजट का योगदान : कैसे और क्यों

1. **दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि** - पूंजीगत व्यय पर जोर देने से तष्टक वृद्धि को स्थायी गति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का गुणक प्रभाव अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में दिखाई देगा।

2. **रोजगार सृजन** - हालाँकि सीधे सरकारी नौकरियों की घोषणा नहीं है, लेकिन निर्माण, रूस्स्थ, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में निवेश से करोड़ों रोजगार के अवसर बनेंगे।

3. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत** - सेमीकंडक्टर, बायो-फार्मा और हाई-टेक विनिर्माण में निवेश भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थान दिलाएगा।

आलोचनात्मक दृष्टि : बजट की सीमाएँ

जहाँ यह बजट दूरदर्शी है, वहीं कुछ कमियाँ भी स्पष्ट हैं- मध्यम वर्ग को प्रत्यक्ष कर राहत का अभाव। महंगाई और शहरी गरीबों के लिए सीमित उपाय। किसानों के लिए एमएसपी और कर्ज राहत। पर स्पष्टता की कमी। लोकतंत्र में विकास के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 को यदि संक्षेप में कहा जाए तो यह 'आज से अधिक कल के भारत का बजट' है। यह तात्कालिक लोकप्रियता से अधिक आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। यदि योजनाओं का ईमानदार क्रियान्वयन हुआ और केंद्र-राज्य समन्वय बना रहा, तो यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

शहीद दिवस पर विशेष

लहू से सींची धरती

(ओजपूर्ण कविता)

लहू से सींची धरती ने आज़ादी का फूल दिया,
हर बलिदान ने भारत को, स्वाभिमान का मूल दिया।
सत्य, अहिंसा, करुणा लेकर जो युग को दिशा दे गए,
महात्मा गांधी के सपनों में, करोड़ों भारत बस गए।
गोली से तन झुका होगा, विचार कभी झुके नहीं,
बापू के सत्याग्रह से, साम्राज्य के शीश टिके नहीं।
भगत सिंह हँसते-हँसते, फाँसी पर झूल गए,
राजगुरु की गोली से, गुलामी के भ्रम टूट गए।
सुखदेव के आदर्शों ने, चेतना को स्वर दिया,
'इंकलाब' के नारों ने, जन-जन को स्वर दिया।
चंद्रशेखर ने कहा-'मैं आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा',
भारत माँ की आन पर, अंतिम श्वास तक लड़ूँगा।
झाँसी की रानी बनकर, इतिहास स्वयं बोला,
'खूब लड़ी मर्दानी', रण में सिंहनी सा डोला।
सुभाष की हुंकारों से, दिशाएँ काँप उठीं,
'तुम मुझे खून दो', कहते ही, आजादी साँसें लेने लगी।
अनगिनत थे वे वीर सपूत, जिनके नाम न लिखे गए,
पर उनकी राख से ही तो, तिरंगे के रंग सजे।
लंबी रातें, काली जंजीरें, यातनाओं का दौर चला,
पर हर आँसू के पीछे, स्वतंत्रता का सूर्य पला।
और फिर वह ऐतिहासिक पल, जब भारत जाग उठा,
गुलामी की हर बेड़ी टूटी, तिरंगा लहरा उठा।
यह आज़ादी कोई दान नहीं, यह शहादत की गाथा है,
हर साँस में शहीद बसे हैं, यही भारत की परिभाषा है।
आओ शहीद दिवस पर हम, यह संकल्प आज उठाएँ,
उनके सपनों का भारत बनाकर, सच्ची श्रद्धांजलि चढ़ाएँ।

- दीपक पचौरी 'दीप'

परमहंस शांतिधाम आश्रम गंगई में विराट कवि सम्मेलन संपन्न

गंगाई ।

श्री परमहंस शांति धाम आश्रम गंगाई में चल रहे सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के पर अंतरराष्ट्रीय संस्था एवं संस्कारधानी के स्वर संस्था के संयुक्त तत्व अवधान में विराट कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। जिसमें आयोजक पं. ब्रम्हानंद जी महाराज ने कहा की साहित्य समाज का दर्पण होता हैं, और कवि ही मानस की आवाज को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है ऐसे सरस्वती पुत्रों का अभिनंदन है। इस अवसर पर कथा व्यास पं. श्री कृष्णा शरल जी महाराज एवं पं. ब्रह्मानंद तिवारी जी का प्रसंग संस्था एवं संस्कारधानी के स्वर के द्वारा 'वाङ्मय भूषण अलंकार' से सम्मानित किया गया। विराट कवि सम्मेलन में कवियों ने अध्यात्म ,भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की श्रेष्ठ कविताओं का पाठ कर पूरा वातावरण साहित्यमय कर दिया वरिष्ठ शायर विनोद नयन जी ने अपनी गजल 'भगवाओ में वह रहा हूँ मैं,इस लिय दर्द सह रहा हूँ मैं' कवि अर्पित पांडे ने 'एक रोटी ने याद भुला दी है सबकी, लेकिन घर की याद भुलाना मुश्किल होगा' शायर विजय आनंद 'माहिर' ने अपनी गजल 'घर वालों का इतना भी तो खौफ ना हो , बच्चे अपनी बात छुपाने लग जाएं'।

कवि डॉ सतेंद्र मालगुजार ने 'इतनी दौलत भी कहां बादशाहों के खजानों में जितनी हमने पाई है मां-बाप के पांव दबाने में' कवि शशांक 'अंकुर' ने बस इसी सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब, बड़ों के चरण छूकर

जीवन यशस्वी हो जाएगा। युवा कवयित्री मानसी मिश्रा ने खुदको जानना है,खुद को पहचानना है ।खुद की तलाश में ,खुद को तराशना है डॉ. प्रशांत मिश्रा ने अपनी कविता उम्र भर निभानी पड़ती है असंख्य मर्यादाएं, एक दिन में यूं ही कोई राम बन नहीं जाता। कवि अरिहंत अमन ने कार्य सेवकों और संतों ने वर्षों तक संघर्ष किया वर्ना सत्ता रामलला को कभी नहीं ला सकती थी तथा कवि अनुराग दुबे ने ऐसे बच्चों का व्यर्थ है जीवन,जिनको मां बाप बोझ लगते है ।

आदि रचनाकारों ने एक से बढ़कर एक कविताओं का पाठ कर श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। संपूर्ण आयोजन का संचालन अजय मिश्रा अजेय ने तथा आभार पुष्पलता तिवारी ने किया।इस अवसर पर परमहंस शांति धाम आश्रम गंगई परिवार के सदस्य विनोद मिश्रा,अशोक चौबे, रतन तिवारी,श्याम तिवारी, राम पटेल,अजय पटेल, संजय परोहा, राजेश मिश्रा कल्याण सिंह ठाकुर आदि उपस्थिति रहे।

शिक्षा संवाद को नई दिशा दे रहा 'टीचर्स ऑफ बिहार'

पटना।

राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बीते कुछ वर्षों के दौरान शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी और वैचारिक चेतना में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। इसी बदलाव की पृष्ठभूमि में टीचर्स ऑफ बिहार एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जिसने शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर शिक्षा नीति, नवाचार और शिक्षक अधिकारों पर संवाद के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराया है।

टीचर्स ऑफ बिहार की पहचान एक ऐसे शिक्षक समूह के रूप में बन रही है, जो बिना किसी औपचारिक संस्थागत दबाव के सहयोग, अनुभव-साझाकरण और रचनात्मक पहल को प्राथमिकता देता है। मंच से जुड़े शिक्षक डिजिटल माध्यमों के ज़रिये न केवल अपने नवाचार साझा कर रहे हैं, बल्कि सरकारी विद्यालयों की जमीनी चुनौतियों पर भी गंभीर और सार्थक विमर्श कर रहे हैं।

डिजिटल संवाद से बढ़ी भागीदारी

मंच की गतिविधियों में ऑनलाइन बैठकें, शैक्षणिक चर्चाएँ और नवाचार आधारित संवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक भी मुख्यधारा के शैक्षणिक विमर्श से जुड़ पा रहे हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सहभागिता शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सहभागी और प्रभावी बना रही है।

सम्मान से अधिक सशक्तिकरण पर जोर

टीचर्स ऑफ बिहार की विशेषता यह है कि यह मंच औपचारिक सम्मान या पुरस्कार

संगठन नहीं, विचार बना शिक्षक सशक्तिकरण का मंच

की बजाय शिक्षक की व्यावसायिक गरिमा, अधिकार और कार्य की गुणवत्ता को महत्व देता है। मंच से जुड़े शिक्षकों का मानना है कि शिक्षक का वास्तविक सम्मान उसके कक्षा-कक्ष में किए गए नवाचार और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर से तय होता है।

नीतिगत विषयों पर सक्रिय भूमिका

शिक्षा से जुड़े नीतिगत निर्णयों, शिक्षक हितों और विद्यालयी सुधार से संबंधित विषयों पर टीचर्स ऑफ बिहार समय-समय पर अपने विचार सार्वजनिक करता रहा है। इससे यह मंच शिक्षक और नीति-निर्माण के बीच संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी उभर रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

शैक्षणिक जानकारों के अनुसार, यदि ऐसे शिक्षक-आधारित मंचों को रचनात्मक समर्थन मिलता रहा, तो यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन का मजबूत आधार बन सकते हैं।

टीचर्स ऑफ बिहार आज एक संगठन से आगे बढ़कर शिक्षा परिवर्तन के साझा विचार के रूप में स्थापित हो रहा है, जहाँ शिक्षक केवल श्रोता नहीं, बल्कि परिवर्तन के सक्रिय भागीदार हैं।

पदाधिकारियों के विचार

टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार एवं टेक्निकल टीम लीडर ई. शिवेंद्र प्रकाश सुमन ने संयुक्त रूप से कहा कि यह मंच शिक्षकों की सामूहिक शक्ति और सकारात्मक सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक सशक्तिकरण को मजबूती देना है।

वहीं प्रदेश प्रवक्ता रंजेश कुमार एवं प्रदेश मीडिया संयोजक मृत्युंजय कुमार ने कहा कि टीचर्स ऑफ बिहार निरंतर संवाद, नवाचार और सहयोग के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में रचनात्मक बदलाव की दिशा में कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, टीचर्स ऑफ बिहार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा में परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि शिक्षकों की जागरूक भागीदारी, संवाद और नवाचार से संभव है। यह मंच शिक्षकों को संगठित करने के साथ-साथ उन्हें सोचने, बोलने और बदलाव का नेतृत्व करने का अवसर दे रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे शिक्षक-आधारित मंचों को निरंतर समर्थन और सकारात्मक दिशा मिलती रही, तो बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था आने वाले वर्षों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के नए मानक स्थापित कर सकती है। टीचर्स ऑफ बिहार आज एक संगठन नहीं, बल्कि शिक्षा परिवर्तन का साझा संकल्प बन चुका है, जहाँ शिक्षक स्वयं बदलाव के सूत्रधार हैं।

नजूल स्थाई पट्टों का नवीनीकरण करने चलेगा अभियान

पट्टाधारकों को दिये जायेंगे नोटिस

सात दिन के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं देने पर शासन में भूमि वेष्ठित करने होगी कार्यवाही

शहर में 20 हजार पट्टाधारकों ने नहीं कराया नवीनीकरण

जबलपुर।

शहर के सभी नजूल पट्टों का नवीनीकरण करने अभियान चलाया जायेगा। इसके तहत ऐसे सभी पट्टाधारकों को नोटिस जारी किये जायेंगे, जिन्होंने अभी तक नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराया है। नोटिस के बाद भी नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं करने पर पट्टाधारकों के विरुद्ध पुन: प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

यह जानकारी आज अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत की अध्यक्षता में जिला पंचायत में संपन्न हुई राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि जबलपुर शहर में ऐसे लगभग 20 हजार स्थाई पट्टे हैं, जिनका नवीनीकरण शेष है।

अपर कलेक्टर श्री गहलोत ने बैठक में कहा कि नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले सभी पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेजों सहित सात दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाये। इसके बावजूद भी यदि पट्टाधारक नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो पट्टे पर उसे दी गई भूमि को शासन के हित में वेष्ठित करने (पुन: प्रवेश) की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

बैठक में अपर कलेक्टर ने ऐसे सभी प्रकरणों में भी अर्थदंड एवं भू-भाटक सहित डायवर्सन का प्रकरण तैयार कर पुन: निर्धारण की कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को दिये जिनमें भूमि स्वामियों द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 59 का उल्लंघन कर उपयोग परिवर्तन कर लिया गया है। श्री गहलोत ने बैठक के माध्यम से शहर के ऐसे सभी नजूल स्थाई पट्टाधारकों से पट्टों का यथोचित समय पर नवीनीकरण कराने का अनुरोध किया है, जिन्होंने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है।

इन दस्तावेजों के साथ करना होगा नवीनीकरण के आवेदन

नजूल स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के लिये पट्टाधारकों को अपने आवेदन में जिन दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा, उनमें पुराना पट्टा (फार्म एच, फार्म एफ एवं फार्म आ), पुराना पट्टा न होने की स्थिति में वर्ष 1955 से अभी तक के नजूल खसरे की सत्यापित प्रति, समस्त आहरण संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्री, लिंक रजिस्ट्री, दानपत्र, वसीयत नामा एवं अन्य दस्तावेज) नामान्तरण आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि, व्यवसायिक भू-खण्ड के नवीनीकरण के लिये नगर तथा ग्राम निवेश का भूमि उपयोग मद, व्यावसायिक भू-खण्ड की स्थिति में व्यवसाय का विवरण देते हुये शपथ पत्र 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, वर्तमान नजूल संधारण खसरा जिसकी नकल आवेदन तीन माह से पूर्व की न हो, दिनांक और समय सहित गूगल लोकेशन के साथ प्रिंट स्थल का मानचित्र (फोटो), नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अप्रूव्ड नक्शे की प्रति, नगर निगम टैक्स रसीद एवं समस्त आवेदकों के आधार कार्ड।

नवीनीकरण के लिये राजस्व निरीक्षक से करना होगा संपर्क

नजूल स्थाई पट्टे नवीनीकरण के लिये पट्टाधारक राजस्व निरीक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। सिटी ब् लॉक 1 से 15 एवं 76 से 80 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक प्रवीण दुबे से, सिटी ब् लॉक 16 से 39 पट्टाधारक लटोरी सिंह, सिटी ब् लॉक 40 से 45 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक अम् बकेश् वर बढ़गैया, सिटी ब् लॉक 46 से 55 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक रिपुदमन सिंह, सिटी ब् लॉक 56 से 75 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक सुयोग् य श्रीवास् तव, सिटी ब् लॉक 81 से 111 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक दलगंजन यादव, सिटी ब् लॉक 112 से 130 एवं सिविल स् टेशन 12 से 21 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक गौरव सिंह, सिटी ब् लॉक 131 से 150 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक रवीन् द्र सिंह, सिविल स् टेशन 1 से 11 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक उमेश कुशवाहा, सिविल स् टेशन 21 से 43 के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक नीतेश तिवारी, गोरखपुर नजूल के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक रमेश साहू, रविशंकर सेन एवं अमित दुबे, गोरखपुर डायवर्जन के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक महेन् द्र साहू, अंकित शुक् ला, विश् वास भंडारी, रमेश साहू, रविशंकर सेन एवं अमित दुबे, आधारताल डायवर्जन के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक अम् बकेश् वर बढ़गैया, सुयोग् य श्रीवास् तव एवं श्रीमती सुरभि जैन से तथा रांझी डायवर्जन के पट्टाधारक राजस्व निरीक्षक कैलाश उर्वेती एवं शैलेष श्रीवास् तव से नजूल स्थाई पट्टे के नवीनीकरण के लिये संपर्क कर सकते हैं।

रेलवे में कैडर-श्रेणी विलय के विरुद्ध अभ्यावेदन

जबलपुर। ईआरएमसी के अध्यक्ष व एनएफआईआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.बिनोद शर्मा ने प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता को उनके कार्यालय से एक दिशानिर्देश जारी करने का प्रतिवेदन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी मंडलों में, कभी-कभी टुकड़ों में और कभी-कभी संयुक्त विभागीय तरीके से बिजली, यांत्रिक, सिविल इंजीनियरिंग तथा सिग्नल एवं दूर-संचार विभागों में विभिन्न कैडरों/श्रेणियों के विलय का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इससे इन कैडरों के कर्मचारियों में भ्रम एवं चिंता फैल रही है और कर्मचारी मान्यता प्राप्त श्रम निकाय के रूप में कर्मरत ईआरएमसी को अभ्यावेदन दे रहे हैं। हमारे श्रमिक संगठन के केन्द्रीय पदाधिकारी और शाखा सचिव भी इस मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, ईआरएमसी प्रस्ताव करती है कि प्रशासन इस विषय पर एक नीति ईआरएमसी के साथ साझा करे, जो रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित विलय के मानदंडों के अनुरूप हो और कर्मचारियों के वैध अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्हें किसी भी तरह से, वरिष्ठता या पदोन्नति के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। डॉ.शर्मा ने माँग की कि कृपया इस विषय में संबंधित विभागों को उनके कार्यालय से एक दिशानिर्देश जारी किया जाए। उन्होंने इसकी प्रतिलिपि मंडल रेल प्रबंधक / पूर्व रेलवे/हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पानी पाउच की अवैध फैक्ट्री बंद कराई

जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुये सिहोरा में सिविल कोर्ट के पीछे, वार्ड कमांक-11 स्थित पानी पाउच की अवैध फैक्ट्री को बन्द करा दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर पानी को आर ओ फिल्टर किये बिना अस्वच्छता के मध्य और बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये पैक किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री की पैकिंग मशीन को सील कर 15 बोरी पाउच जप्त किये गये।

बॉर्डर में दमखम दिखाने व्हीएफजे से रवाना हुए टी-72 टैंक्स

निर्माण के बाद हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) की इकाई, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (व्हीएफजे) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओवरहॉल किए गए पहले दो टी-72 टैंकों को विगत दिवस एक समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजैला, मास्टर जनरल सस्टिनेंस (एमजीएस) द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समारोह में एवीएनएल के सीएमडी संजय द्विवेदी, सत्यब्रत मुखर्जी, डायरेक्टर ऑपरेशंस एचआर, मेजर जनरल प्रभजोत सिंह भाटी/एडीजी, मेजर जनरल आरएस सुंदरम/एडीजी, प्रवीण कुमार, सीजीएम आदि शामिल हुए। भारतीय सेना के लिए बैटल टैंक ओवरहॉलिंग की बढ़ी हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए एवीएनएल ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स में से एक व्हीएफजे को चुना, ताकि एवीएनएल की इकाई हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में मौजूदा ओवरहॉल सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इस क्षमता विस्तार पहल के हिस्से के रूप में 2025 में टैंकों का पायलट ओवरहॉल करने की मंज़ूरी दी गई थी। व्हीएफजे ने भारतीय सेना द्वारा तय किए गए तकनीकी विशिष्टियों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार टैंकों का ओवरहॉल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो सेना की ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा करने की अपनी क्षमता और तैयारी को दिखाता है।

सफल ओवरहालिंग के लिए दी बधाई

समारोह में संजय द्विवेदी, सीएमडी/एवीएनएल ने व्हीएफजे द्वारा निर्धारित समय सीमा में टैंकों को सफलतापूर्वक ओवरहॉल किए जाने पर अपनी शुभकामनाएं दी और एवीएनएल के मुखिया होने के नाते यह संकल्प दोहराया कि एवीएनएल, व्हीएफजे पूरी क्षमता के साथ टैंकों की ओवरहालिंग सुनिश्चित करते रहेगा। समारोह के मुख्य अतिथि ल्यूटनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजेला ने पूरी एवीएनएल और व्हीएफजे की टीम को प्रथम दो टैंकों की सफल ओवरहालिंग के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसे तय समय पर पूरा करके आपने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। आगे भी आपको टैंकों की ओवरहालिंग का बड़ा काम मिलेगा । इसके पहले अपने स्वागतीय उद्बोधन में निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा सबको विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार दो टी-72 टैंक हमने तय समय के भीतर ओवरहाल कर लिए हैं, और आगे भी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ टैंकों की ओवरहाल करते रहेंगे।

समाज को बांटने का कार्य कर रही सरकार

यूजीसी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने लगाए आरोप

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने विगत दिवस यूजीसी कानून के विरोध में घंटाघर के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि यह कानून ऐसा दर्शाता है मानो देश में अन्य जातियों पर हो रहे अत्याचारों के लिए सवर्ण समाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। ब्राह्मण समाज ने बताया कि 2012 में भी यूजीसी कानून लागू था। उस समय यह स्पष्ट प्रावधान था कि यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मौजूदा कानून में इस प्रावधान की कमी पर सवाल उठाया।

देशव्यापी आंदोलन की तैयारी

ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाते हुए बताया गया कि एक ओर सरकार में बैठे लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे कानून लाकर समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। ब्राह्मण महासभा ने घोषणा की है कि आगामी एक फरवरी को यूजीसी कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसे ब्राह्मण महासभा का समर्थन रहेगा।

विकसित भारत की दिशा में जनहितैषी और दूरदर्शी केंद्रीय बजट : प्रोमिला पूनिया

हरियाणा/हिसार। प्रोमिला पूनिया वरिष्ठ भाजपा नेत्री, हिसार ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट देश के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। इस बजट में समाज के हर वर्ग-गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग और व्यापारी-की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री प्रोमिला पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार महिला हितैषी है आज निर्मला सीतारमण ने नोवी बार बजट प्रस्तुत किया। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र को मजबूती, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है, जिससे देश की मानव संसाधन क्षमता और अधिक सशक्त होगी।

किसानों के हित में किए गए प्रावधान कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। वहीं मध्यम वर्ग को कर राहत और व्यापारियों को उद्योग एवं स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएंगी। प्रेमिला पूनिया हिसार ने बताया कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें दीर्घकालिक विकास, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समरसता का संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

कथक के माध्यम से अनेक कथाओं का भावभरा प्रस्तुतीकरण

राधाछवि कथक नृत्य महोत्सव में मंत्रमुग्ध हुए दर्शक

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सुप्रसिद्ध कथक नर्तक-नृत्यांगनाओं के साथ ही नगर के ख्यातिलब्ध नृत्य गुरुओं और उनके शिष्यों ने नवरंग कथक कला केंद्र द्वारा शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित अ.भा. राधाछवि कथक नृत्य महोत्सव में नृत्यों का ऐसा समा बंधा की दर्शक तीन घंटे तक मंत्रमुग्ध अपने स्थान पर बैठे रहे । हर प्रस्तुति के उपरांत देर तक तालियां गूंजती रहीं।

खैरागढ़ के नृत्यगुरु डॉ. सम्राट चौधरी एवं सतना की कु. सुकृति सोनी ने मनोहारी एकल नृत्य प्रस्तुत किए । गुवाहाटी की युगस्मिता गोस्वामी एवं कौशिक दत्ता ने युगल नृत्य प्रस्तुत किया। नगर की श्रीमती स्वाति मोदी तिवारी, डॉ. उपासना उपाध्याय, श्रीमती मेघा पांडेय एवं मोती शिवहरे के निर्देशन में सामूहिक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे । कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी पगलानंद जी महाराज, महापौर जगतबहादुर सिंह 'अन्नू', अजय विश्नोई, रिंकू बिज, सहित अशोक मनोध्या, प्रतुल श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, मीना विश्वकर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। मंगला चरण रोहित दुबे,कामता तिवारी ने किया। अतिथियों का स्वागत मोती शिवहरे, डॉ. प्रकाश दुबे, विनीता, सारंग, डॉ. रजनीश गर्ग, लायन नरेंद्र जैन, आलोक पाठक ने मोतियों की माला, साफ़ा एवं श्रीफल भेंट करके किया चित्रकार प्रमोद कुशवाहा ने सभी को स्व निर्मित कलाचित्र भेंट किए। अतिथियों ने नृत्य महोत्सव को नगर का अद्वितीय समारोह बताते हुए सभी कलाकारों की प्रशंसा की। संचालन राजेश पाठक 'प्रवीण' एवं मोती शिवहरे ने तथा आभार विजय जायसवाल ने व्यक्त किया।

समारोह में गुंजन कला सदन एवं पाथेय संस्था की सहभागिता रही। दोनो संस्थाओ ने मोती शिवहरे को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में उपस्थिति

इस अवसर पर संस्कार भारती परिवार के सदस्य एडवोकेट मदन पटेल, पत्रकार संजय सागर सेन, एडवोकेट रवि सोनी, सुशील उपाध्याय, कमलेश यादव, कृष्ण कुमार तिवारी, श्रीमती सी.पी. वैश्य आदि विषेश रूप से उपस्थित रहे।

गूंज अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आयोजना बच्चे बनकर आए नेता जी सुभाषचंद्र बोस

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

शहीद स्मारक, जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में शिक्षाविद अजय शर्मा गूंज अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था आयोजक माधुरी उमेश मिश्रा जादूगर. एस. के. निगम विवेक रंजन शुक्ला ने सुभाष वेशभूषा में आए 200 बच्चों को मेडल प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया द्य आयोजन में युवा ऊर्जा चिंटू त्रिपाठी स्मृति को नमन किया गया एवं युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया साथ ही युवा ऊर्जा मधुमेश मिश्रा को मीना हरि प्रसन्न त्रिपाठी जी द्वारा सरस्वती मां की बड़ी मूर्ति भेंट की गई द्य युगपुरुष सुभाष चंद्र बोस सम्मान गूंज अंतर्राष्ट्रीय संस्था संस्थापक माधुरी उमेश मिश्रा एवं विवेक शुक्ला द्वारा दिया गया जगतगुरु राघव देवाचार्य जी को कलाकारों ने देश भक्ति गीतों से सभी का दिल जीता शानदार संगीत के साथ दिनेश खड़तिया गूंज के संगीत संयोजक ने गीतों के कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सर्वप्रथम भारत माता की आरती डॉ .हरीशंकर दुबे डॉ. बैजनाथ गौतम पंडित रूद्रदत्त दुबे डॉ आर एस शिवहरे मनोहर चौबे आकाश सुशीला चौबे, संध्या व्यौहार राजलक्ष्मी शिवहरे के कमलों द्वारा प्रारंभ हुई।

कार्यक्रम में डॉ. अनिल बाजपेई, सुशील श्रीवास्तव, अर्चना गोस्वामी, डॉ. नेहा खरे, विनोद स्वामी, सुमन अग्रवाल हे प्रीत जहां, हर करम अपना करेंगे, कमल बघेल, मेरे देश की धरती, संजय पाठक, देखो वीर जवानों, अनिल कोरो, विनीता पैगवार मयंक विश्वकर्मा, मनोज निनोरिया, डॉ. पूनम शर्मा, दुर्गेश व्यौहार, भारत माता की आरती, अफजल, सुनो गौर से दुनिया, रचना श्रीवास्तव, ए मालिक तेरे, मनीष श्रीवास्तव, और ये देश है वीर जवानों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी द्य

इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया गया, जो उनकी 129वीं जयंती थी कार्यक्रम का संचालन माधुरी उमेश मिश्रा राजेश पाठक प्रवीण द्वारा किया गया आभार प्रदर्शन नीरज शुक्ला द्वारा किया गया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से शुरू हुआ स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान

घर-घर होगी कुष्ठ रोगियों की पहचान एवं जांच

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरुकता अभियान का शुभारंभ आज जिला चिकित्सालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर किया गया। एक पखवाड़े का यह अभियान 13 फरवरी तक चलाया जायेगा। अभियान के तहत घर-घर जाकर कुष्ठ रोगियों की खोज एवं जाँच की जायेगी। कुष्ठ रोग को लेकर आमजन में फैली भ्रांतियों का निदान किया जायेगा तथा प्रचार-प्रसार, पीओडी कैंप आदि गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शक्ति खरे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने की अन्य अतिथियों के तौर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष डॉ ऋचा शर्मा, सक्षम संस्था प्रकोष्ठ महाकौशल प्रांत के सचिव डॉ पीयूष जैन, लायंस क्लब की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा सोनी, लायंस क्लब जिला सचिव उमेश जैन, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ नवीन कोठारी, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ पारस ठाकुर, डॉ संजय जैन, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ निश्चय सक्सेना, डॉ आशीष राय, लीगल सेल से श्री बी डी दीक्षित, आरएमओ डॉक्टर वैशाली खन्ना, जिला मीडिया अधिकारी अजय कुरील मौजूद थे।

कार्यक्रम की प्रथम कड़ी मे उपस्थित जिले के कुष्ठ मरीजों एवं अन्य जिलों से आए आरसीएस (सर्जरी) के मरीजों का लायन्स क्लब की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा सोनी एवं अन्य अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। लायंस क्लब द्वारा जबलपुर कुष्ठ विभाग की टीम तथा जिला चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया तथा कुष्ठ रोगियों को दी जा रही सेवाओं के लिए प्रशंसा की।

शासन द्वारा कुष्ठ मरीजों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन योजनाओं की जानकारी मरीजों एवं उनके परिजनो को जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ पारस ठाकुर द्वारा दी गई। विकृति से बचाव व आर-सी-एस (सर्जरी) के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी सिविल सर्जन तथा आरसीएस सर्जन डॉ नवीन कोठारी के द्वारा दी गई।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन में नागरिकों से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। शपथ का वाचन सिविल सर्जन डॉ नवीन कोठारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन एनएमएस आर के चौबे के ने किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कुष्ठ विभाग एवं जिला चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा।

बरगी बांध की मुख्य दाईं तट की नहर टूटने से मचा हड़कंप, फसलों को भारी नुकसान

शिकायतों के बाद भी नहीं हुआ था सुधार, कलेक्टर ने दिए सर्वे के निर्देश

बरगी थाना क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दोपहर लगभग 12 बजे बरगी बांध की मुख्य दाईं तट नहर ग्राम सगड़ा-झपनी के पास टूट गई। नहर टूटते ही तेज बहाव के साथ पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिससे किसानों की खड़ी फसलें डूब गईं।

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

देखते ही देखते खेत तालाब में तब्दील हो गए और ग्रामीणों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया।

एहतियात के तौर पर बरगी बांध की दाईं तट नहर से पानी की निकासी पूरी तरह बंद करा दी गई। साथ ही टूटे हिस्से के आगे के सभी नहर गेट खोल दिए गए, ताकि खेतों में भरे पानी की तेजी से निकासी हो सके और नुकसान को और बढ़ने से रोका जा सके।

मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला- इस मामले में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि नहर की हालत लंबे समय से खराब थी। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि पहले ही सुधार कार्य हो जाता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती और किसानों को भारी नुकसान से बचाया जा सकता था। घटनास्थल पर एसडीएम अभिषेक सिंह, बरगी बांध दाईं तट नहर के कार्यपालन यंत्री सहित प्रशासनिक और तकनीकी अमला पहुंचा। जिन्होंने नहर के टूटे हिस्से का निरीक्षण किया। साथ ही अस्थायी मरम्मत के साथ स्थायी समाधान की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कलेक्टर ने दिए फसलों के सर्वे के निर्देश

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व और कृषि विभाग की टीम किसानों के खेतों का निरीक्षण कर रही है, ताकि नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा सके। इसके आधार पर आगे मुआवजे की प्रक्रिया तय की जाएगी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि किसानों को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा है। प्रभावित किसानों ने मांग की है कि उन्हें शीघ्र मुआवजा दिया जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए।

सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की रिकवरी निकालना नियमों के विरुद्ध

याचिका पर मप्र हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, पेंशनर्स को बड़ी राहत

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

मप्र हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की रिकवरी (वसूली) निकालना नियमों के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए भविष्य में ऐसी कार्रवाई न दोहराने की बात कही है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पेंशन अधिकारी पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) जारी करते समय नियमित रूप से वसूली के आदेश पारित कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वे प्रदेश के सभी जिलों के पेंशन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। इस निर्देश का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकना और सेवानिवृत्त कर्मियों को मानसिक व आर्थिक परेशानी से बचाना है।

सेवानिवृत्ति के बाद वसूली अवैध

दरअसल यह मामला जबलपुर निवासी रोहणी प्रसाद पटेल की याचिका पर सुना गया, जो 2017 में सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सचिन पांडे ने दलील दी कि विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद वसूली के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह और हाई कोर्ट के जगदीश प्रसाद प्रकरणों का हवाला देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती, भले ही कर्मचारी ने सेवा के दौरान कोई अंडरटेकिंग (वचन पत्र) भरी हो।

ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश

मप्र हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी रिकवरी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता से अब तक कोई वसूली की गई है, तो वह राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिन के भीतर लौटाई जाए। मप्र हाईकोर्ट के इस कड़े रुख से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

डैम में फंसा मिला अधेड़ का शव

जबलपुर। पनागर थाने में सुदेश कुमार दाहिया उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मुहारी पनागर ने सूचना देकर बताया कि वह ग्राम का कोटवार है। सुबह के वक्त अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे सूचना मिली कि मुहारी डेम में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव डेम में फसा हुआ है। वह मुहारी डेम जाकर देखा तो एक अज्ञात व्यक्ति का शव डेम में फसा हुआ था जिसका सिर दिख रहा था। सूचना पर मर्ग कायम कर अज्ञात मृतक की शिनाखत्गी कि प्रयास किये गये।

चौथी मंजिल से गिरकर फिजियोथैरेपिस्ट की मौत

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर क्षेत्र में बनी यश हाइट अपार्टमेंट नामक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। शुरुआती जांच में पुलिस को बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय डॉ. भानु मोहर निवासी दतिया के रूप में हुई है। जो (बीपीटी) फिजियोथैरेपी की पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस कर रहा था। इस मामले में सीएसपी गोरखपुर एमडी नागोतिया ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली थी कि अपार्टमेंट में रहने वाले युवक ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एक सुरक्षाकर्मी समेत आसपास के लोग मौजूद थे। जांच में पता चला कि भानू पिछले करीब छह महीने से यश हाइट्स में किराए के फ्लैट में अकेला रह रहा था।

कमरे को किया सील- मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि डॉ. भानु साल 2019 बैच का छात्र था। उसने बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (बीपीटी) की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। डॉ. भानु अक्टूबर 2025 में पास आउट होने के बाद किराए के मकान में अलग रह रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पीएम के लिए भिजवाते हुए उसके कमरे को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मप्र हाईकोर्ट ने निरस्त की अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। मप्र हाईकोर्ट ने एक आदेश में अधिवक्ता सुभाष तिवारी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया है। दरअसल यह मामला थाना सोहागी, जिला रीवा में दर्ज अपराध से संबंधित था। जिसमें अधिवक्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि सार्वजनिक स्थान पर शिकायतकर्ता की फोटो खींचकर उसे बदनाम करने की धमकी दी गई। जिससे संबधित एफआईआर को न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी ने दर्ज अपराध को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल भट्ट एवं धीरेन्द्र मिश्रा ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि एफआईआर एवं धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अधिवक्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से धारा 509 आईपीसी के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते। हाईकोर्ट के समक्ष ये तथ्य भी रखा गया कि याचिकाकर्ता एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता है तथा उसके विरुद्ध पेशेगत शत्रुता एवं व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते विलंब से एफआईआर दर्ज की गई थी।

रहवासी इलाके में कई दिनों से भटक रहा चीतल

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

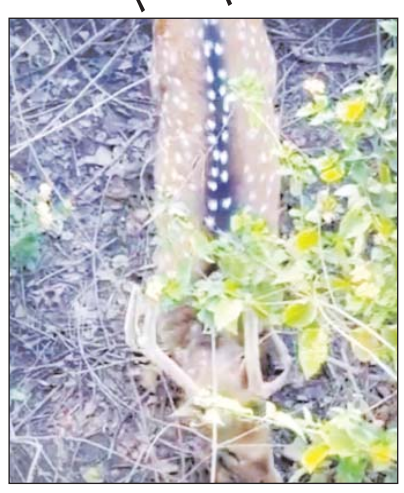

शहर में तेजी से बढ़ती आबादी के चलते अब जंगली जानवर भी शहर का रुख कर रहे हैं। शहर के आवासीय क्षेत्र महाराणा प्रताप वार्ड स्थित धन्वंतरी नगर में बीते तीन दिनों से एक चीतल जंगल से भटककर रहवासी इलाके में आ गया है। इसके चलते जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं चीतल भी दिनभर इधर-उधर भटकता नजर आ रहा है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन तीन दिनों से विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रहवासियों ने पुलिस को भी सूचना दी। जिसके बाद वन विभाग को फिर से जानकारी दी गई। इसके बावजूद जब वन विभाग ने रेस्क्यू नहीं किया तो कलेक्टर को अवगत कराया गया। लोगों ने बताया कि यह चीतल कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है। पहले यह परसवाड़ा से लगे जंगल में दिखाई देता था, लेकिन बीते तीन दिनों से रहवासी इलाके में आ गया है। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द ही वन विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो चीतल की मौत या तो सड़क दुर्घटना में हो सकती है या फिर कुत्तों का शिकार बन सकता है। क्षेत्री लोगों ने बताया कि दो दिन पहले भी वन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची है। इससे चीतल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में घूम रहे आवारा कुत्तों से चीतल को लगातार खतरा बना हुआ है।

निगमायुक्त ने की 6 घंटे लंबी मैराथन बैठक

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, कंसल्टेंट और ठेकेदारों की एक 6 घंटे लंबी मैराथन समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में 9 प्रमुख विभागों के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई और निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्थापना, पेंशन, स्वास्थ्य, विद्युत, जल, उद्यान, लोककर्म, योजना, शासकीय योजना विभाग के कार्यों की बारी-बारी से जानकारी ली और सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित प्रस्तावित एवं प्रचलित कार्यों को गंभीरता के साथ उच्चगुणवत्ता और समय सीमा में पूर्ण कराएं। कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। निगमायुक्त ने अमृत फेस 1 एवं 2 के कार्यों की समीक्षा कर तेजगति से काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान पी.एम. स्वनिधि योजना के कार्यो की भी समीक्षा की और कार्यो में और गति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने तथा न्यायालयीन प्रकरणों पर भी विधिसम्मत कार्य करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान निगमायुक्त श्री अहिरवार ने निर्देशित किया कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सभी नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रात:काल वार्डो का भ्रमण करने और जमीनी धरातल पर स्थाई रूप से कार्य कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्तों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों और वार्डों का नियमित भ्रमण करने के भी निर्देश दिए।

देह व्यापार के लिए उज्बेकिस्तान से आई महिला पुलिस की गिरफ्त में

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

बड़े देह व्यापार अड्डे का हुआ भांडाफोड़, माढ़ोताल थाना पुलिस की कार्यवाही

शहर चल रहे अवैध देह व्यापार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक अन्य महिला को भी पकड़ा है जो अपने पति के इशारे पर दूसरे देश से महिलाओं को लाकर यहां रहने वाले अमीर लोगों के सामने परोसा करती थी। पुलिस ने मौके से उज्बेकिस्तान महिला के साथ एक अन्य महिला को पकड़ा है, हालांकि इसका मास्टरमाइंड और गिरोह का सरगना मौके से जरूर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि माढ़ोताल थाना के ग्रीन सिटी में बीते कई दिनों से देह व्यापार का खेल चल रहा था, जहां पर कि ना सिर्फ भारत, बल्कि विदेश से भी युवतियां आया करता थी। इस मामले में सीएसपी आशीष जैन को एक मुखबिर ने बताया कि ग्रीन सिटी स्थित एक घर पर जहां कि कुछ लोगों ने किराए पर लिया है, वहां पर कुछ अनैतिक गतिविधियों के साथ ऐसे लोग भी आते हैं,जिनकी हरकत आपत्तिजनक है। हर बार यहां आने वाले लोग किसी महिला या फिरयुवती को लेकर आते हैं। पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय के निर्देश पर सीएसपी आशीष जैन और महिला थाना पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसे दिल्ली के रास्ते प्लेन तो कभी ट्रेन से जबलपुर लाया गया था। महिला ने बताया कि वह 2011 में उसका विवाह हुआ था। पति की मौत के बाद वह इस गौरखधंधे में उतर आई। महिला का कहना है कि 2023 में पति की मौत के बाद वह मुंबई आ गई, यहां पर उसने दूसरी शादी की। इसी दौरान दिल्ली निवासी प्रिया कौर से सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई।

अन्य महिला की हुई गिरफ्तार

महिला का कहना है कि कुछ दिनों पहले शिव चौधरी और उसकी पत्नी सुषमा चौधरी से उसकी दोस्ती हुई, इसके बाद ट्रेन से उसे शुक्रवार को जबलपुर बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उज्बेकिस्तान से मुंबई आने के बाद जब शिव चौधरी से दोस्ती हुई तो उसने देह व्यापार में कमाई के लिए अच्छी खासी रकम दिलाने का आश्वासन दिया और जबलपुर बुला लिया। पुलिस ने विदेशी महिला के साथ सुषमा चौधरी नाम की महिला को भी हिरासत में लिया है, हालांकि महिला का पति शिव चौधरी जिसने की ग्रीन सिटी में 15 दिन पहले ही किराए से मकान लिया था। वह फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सीएसपी आशीष जैन ने बताया कि मुख्य आरोपी शिव चौधरी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी की पत्नी हनुमानताल निवासी है, जो कि पति के कहने पर ग्रीन सिटी में किराए का मकान लेकर रह रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि विदेशी महिला एक दिन पहले ही जबलपुर आई थी।

शहर के कई हिस्सों में है ठिकाना

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि शिव चौधरी आदतन अपराधी है, जो कि शहर के कई ठिकानों में किराए के मकान लेकर देह व्यापार का काम किया करता था। पुलिस को शक ना हो इसके लिए आरोपी पत्नी और बच्चों को भी रखा करता था। जानकारी के मुताबिक जबलपुर शहर के अलावा जिले के कई अन्य इलाकों में भी इसने देह व्यापार का अड्डा खोल रखा है। फिलहाल आरोपी शिव चौधरी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

स्पा सेंटरों पर भी कसेगा शिकंजा

सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि अभी तक उज्बेकिस्तान से आई एक महिला को हिरासत में लिया है। करीब 10 युवतियां शहर लाई गई हैं, वह अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है। लगातार कार्यवाही जारी है। स्पा सेंटर का लाइसेंस नगर निगम से जारी किया जाता है, अब यह भी देखा जा रहा है कि नगर निगम की टीम किस आधार पर स्पा सेंटर को लाइसेंस दे रही है।

खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, एयर बैग ने बचाई जान

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। विगत दिवस सुबह को एक तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई। यह वही स्थान है जहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कार जबलपुर से बारेला की तरफ जा रही थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। बताया जा रहा है कि कार का एयरबैग खुल जाने से कार चालक की जान बच गई है। घटना सुबह 5 बजे की है। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद गोरा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बिजली का खंभा टूटने से इलाके में अंधेरा भी हो गया।

इससे पहले बिलहरी क्षेत्र में भी इसी तरह से हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। घटना देर रात को हुई थी। एक्सीडेंट में जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद मौके पर डायल-112 पहुंची। कार चालक और दुकान मालिक के बीच आपसी समझौता होने के कारण कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संजय सागर सेन द्वारा नेशनल टाईम्स पब्लिकेशन, 262 विकास नगर, कृषि उपज मंडी विजय नगर, जबलपुर म.प्र. से मुद्रित। 737 गुप्ता कॉलोनी, गढ़ा फाटक, कस्तूरबा गांधी वार्ड, जबलपुर मप्र पिन कोड 482002 से प्रकाशित।
संपादक : संजय सागर सेन। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी, टाइटल कोड - एमपीएचआईएन 38088, समस्त प्रकरण जबलपुर न्यायालय के अंतर्गत) Email.sanjayssagar20@gmail.com मो. : 9425867695, 6232060720